(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन बीजों एवं तकनीक को ग्राम किसानों तक पहुंचाने के लिए कोई योजना/व्यवस्था बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान ने टिशु कल्चर तकनीक से सरसों की दो उत्तम प्रजातियों अर्थात् बायो-वाई०एस०आर० तथा बायो-902 का पता लगाया है। इन प्रजातियों की निष्पत्ति के लिए आग और परीक्षण किए जा रहे हैं। दालों के मामले में नई तकनीकों के माध्यम से कोई नई प्रजाति विकसित नहीं की गई है।

(ग) और (घ) यदि सरसों की प्रजातियो की निष्पत्ति मूल्यांकन की विभिन्न अवस्थाओं में अच्छी रही और नियुक्ति तथा अधिसूचना के लिए उनका चयन कर लिया गया तो उनकी वाणिज्यिक खेती के लिए बीज बहुलीकरण किया जाएगा।

ग्रामीण मजदूरों की दैनिक मजदूरी

925. डा० जिनेन्द्र कुमार जैन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में असंगठित ग्रामीण मजदूरों की संख्या 115 मिलियन से भी अधिक है;

(ख) क्या यह भी सच है कि असंगठित मजदूरों की दैनिक मजदूरी विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की जाती है जो भिन्न-भिन्न राज्यों में 8 रुपए 50 पैसे से लेकर 12 रुपए 75 पैसे प्रति दिन है;

(ग) किन-किन राज्यों में इन ग्रामीण मजदूरों की मासिक मजदूरी 600 रुपए या इससे कम है और क्या सरकार द्वारा इन असंगठित और शोषित मजदूरों के कल्याण के लिए कोई कार्य योजना बनाई जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० राममूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) कृषि मजदूरों को छोड़कर विभिन्न अनुसूचित नियोजनों के लिये राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित असंगठित श्रमिकों की दैनिक मजदूरी केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुरक्षित नहीं की जाती है।

(ग) और (घ) जैसा कि ऊपर के भाग (ख) में बताया गया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। केन्द्रीय सरकार ने मई 90 में राज्य सरकारों को लिखा था कि वे किसी भी अनुसूचित नियोजन में न्यूनतम मजदूरी की निम्न सीमा 15 रु० प्रतिदिन से कम निर्धारित न करें। राज्य सरकारों को यह सलाह भी दी गई थी कि वे दो वर्षों में एक बार या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 50 अंकों की बढ़ोतरी होने पर जो भी पहले हो, न्यूनतम मजदूरी की दरों को संशोधित करें।

खान-पान व्यवस्था के संचालन में रेलवे द्वारा उठाई गई हानि

926. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे द्वारा संचालित खान पान व्यवस्था में प्रतिवर्ष भारी हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी आर्थिक हानि हुई है;

(ग) क्या सरकार ने स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(घ) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले;